an>

Title: Regarding non-payment of salaries to teachers under N.C.L.P in Punjab.

श्री स्वनीत सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1988 में नेशनल वाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अधीन एक योजना देश के 12 जिलों में शुरू की गई थी, जो आज 271 जिलों में चल रही है। यह योजना यूपीए सरकार की देन थी। इस योजना के तहत देश में 6000 स्कूल्स में करीब दस लाख ऐसे बच्चें पढ़ रहे हैं जो पहले बाल श्रमिक के तौर पर ईट भट्टों पर, चाय की दुकानों पर, कारखानों और उद्योगों में काम कर रहे थे। उन्हें पढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। लेकिन इन स्कूल्स में जो अध्यापक काम कर रहे हैं, उन्हें 1 साल से वेतन नहीं दिया गया है। हम लोगों को यह चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये स्कूल बंद हो जाएं और जो दस लाख बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं, वे फिर से चाय की दुकानों, फैक्टरीज आदि में काम करना न शुरू कर दें। मैं पंजाब की बात करूं तो वहां लुधियाना में इस तरह के 40 स्कूल्स हैं और उनमें 200 टीचर्स हैं। मैंने खुद तीन स्कूल्स को विजिट किया और देखा कि वहां दर्दनाक स्थिति है। यूपीए सरकार ने 2013-2014 के वित्तीय वर्ष में 55 लाख रुपए भी पंजाब को दिए, लेकिन डेढ़ साल हो गया, उन टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है। अमीर और गरीब के बीच जो यह खाई है, उसे भरना जरूरी है। यह देश गरीबों के लिए भी बराबर का है और उनके लिए भी स्कूल्स बने हैं उनका चलना जरूरी है। मेरा लेबर मिनिस्टर जी से निवेदन है कि इन स्कूल्स के टीचर्स को तुरंत वेतन का भुगतान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भगवंत मान,

श्री राजीव सातव को श्री स्वनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।